Part VI: The States

Part VI of the Constitution of India deals with the States. It contains provisions regarding the administrative, legislative and judicial structure of the States and their relationship with the Union.

Article 3 provides for the creation of new States and the alteration of the boundaries of existing States.

Articles 4 to 7 deal with the laws relating to the formation of new States and alteration of boundaries of existing States, and the power of Parliament to make laws on these matters.

Articles 244 to 244A deal with the administration of tribal areas in the States.

Articles 245 to 255 deal with the distribution of legislative powers between the Union and the States. The State Legislatures have the power to make laws on subjects enumerated in the State List, while the Union Parliament has exclusive powers to make laws on certain subjects enumerated in the Union List.

Articles 256 to 263 deal with the coordination and administration of the States and the Union, and provide for the obligation of the States to comply with the laws made by Parliament and the executive power of the Union to extend to the administration of the States.

Articles 264 to 266 deal with the establishment of the Inter-State Council to promote cooperation and coordination between the States.

Overall, Part VI of the Constitution of India lays down the provisions regarding the administrative, legislative and judicial structure of the States and their relationship with the Union, and seeks to promote cooperation and coordination between the States and the Union.

भाग VI: राज्य

भारत के संविधान का भाग VI राज्यों से संबंधित है। इसमें राज्यों के प्रशासनिक, विधायी और न्यायिक ढांचे और संघ के साथ उनके संबंधों के बारे में प्रावधान हैं।

अनुच्छेद 3 नए राज्यों के निर्माण और मौजूदा राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन का प्रावधान करता है।

अनुच्छेद 4 से 7 नए राज्यों के गठन और मौजूदा राज्यों की सीमाओं के परिवर्तन से संबंधित कानूनों और इन मामलों पर कानून बनाने के लिए संसद की शक्ति से संबंधित है।

अनुच्छेद 244 से 244ए राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है।

अनुच्छेद 245 से 255 संघ और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों के वितरण से संबंधित है। राज्य विधानमंडलों के पास राज्य सूची में शामिल विषयों पर कानून बनाने की शक्ति है, जबकि केंद्रीय संसद के पास संघ सूची में शामिल कुछ विषयों पर कानून बनाने की विशेष शक्तियां हैं।

अनुच्छेद 256 से 263 राज्यों और संघ के समन्वय और प्रशासन से संबंधित हैं, और राज्यों के दायित्व के लिए संसद द्वारा बनाए गए कानूनों का पालन करने और संघ की कार्यकारी शक्ति को राज्यों के प्रशासन तक विस्तारित करने के लिए प्रदान करते हैं।

अनुच्छेद 264 से 266 राज्यों के बीच सहयोग और समन्वय को बढ़ावा देने के लिए अंतर-राज्य परिषद की स्थापना से संबंधित है।

कुल मिलाकर, भारत के संविधान का भाग VI राज्यों के प्रशासनिक, विधायी और न्यायिक ढांचे और संघ के साथ उनके संबंधों के बारे में प्रावधान करता है, और राज्यों और संघ के बीच सहयोग और समन्वय को बढ़ावा देने का प्रयास करता है।